ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज-अस्पताल से 13 प्रोफेसरों के तबादले, पूरी तरह गैरकानूनी

जीडीएमओ गैंग के वर्तमान पालनहार

भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय श्रम मंत्री

आरती आहूजा, आईएएस, श्रम सचिव

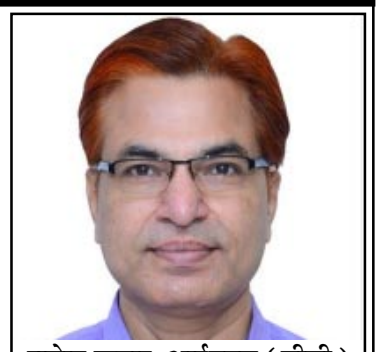

राजेन्द्र कुमार, आईएएस (डीजी)

2021 में गुपचुप तरीके से ट्रांसफर पॉलिसी जीडीएमओ गैंग ने बदल दी जिसे समझने व रोकने-टोकने की जरूरत डीजी, श्रम सचिव व मंत्री ने नहीं समझी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) एनएच तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की गिनती न केवल हरियाणा के बल्कि देश के सर्वोत्तम संस्थानों में होने लगी है। सन् 2015 में इसके शुरू होने से पहले चल रहे यहां के अस्पताल में महज 100-150 मरीज़ दाखिल रहते थे तथा 1200-1400 की ओपीडी चलती थी। आपातकालीन विभाग न के बराबर था। जाहिर है उन हालात में ईएसआईसी को अपने वेतन से पैसा देने के बावजूद उस अस्पताल में मरीज आना पसंद नहीं करते थे। इलाज के अभाव में या तो मरीज मर जाते थे अथवा सिफारिशों के बल पर निजी अस्पतालों में रेफर हो जाते थे।

कॉर्पोरेशन द्वारा इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चलाये जाने के बाद से यहां रोजाना करीब पांच हजार मरीज ओपीडी में आने लगे हैं और 700-800 मरीज़ भर्ती रहने लगे हैं। जाहिर है कि उचित उपचार न मिलने के चलते जो मरीज़ अस्पताल आते ही नहीं थे, बेहतर उपचार उपलब्ध होने के चलते मरीज़ों की संख्या दिन दूनी-रात-चौगुनी बढ़ने लगी। कैंसर से लेकर हृदय रोग तक के वे बेहतरीन उपचार यहां होने लगे जो हरियाणा के किसी भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। कई मामलों में तो यह संस्थान दिल्ली के एम्स का मुकाबला करता है। इन्हीं सब बातों के चलते पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार व उनके कई परिजन यहां दाखिल रहकर इलाज करा चुके हैं। इनके अलावा श्रम मंत्रालय एवं कॉर्पोरेशन मुख्यालय के भी कई उच्चाधिकारी यहां की सेवाएं वर्तमान श्रम मंत्री भूपेन्द्र यादव लेते रहे हैं।

मेडिसन के प्रोफेसर डॉ. प्रवीण मलिक ने, बीते वर्ष यूपीएससी द्वारा केन्द्र सरकार की बेहतर सेवा के लिये चयनित होने के बावजूद मज़दूरों की सेवा के लिये इसी अस्पताल में बने रहने का निर्णय लिया था। परन्तु मुख्यालय में कब्जा किये बैठे गैंग को यह नहीं सुहाया और उठाकर उन्हें अलवर फेंक दिया। रेडियोलॉजी के प्रोफेसर डॉ. जफ़र जिन्हें कोई भी निजी अस्पताल, यहां मिलने वाले वेतन से दोगुने-तिगुने पर लेने को तैयार बैठे हैं; लेकिन उन्होंने मज़दूरों की सेवा करने को अधिक प्राथमिकता दी। इसके इनाम स्वरूप उन्हें यहां से उठाकर बेंगलुरु फेंक दिया है। इनके अलावा अन्य प्रोफेसर साहिबान भी अपने-अपने विषय के महारथी हैं, जिन्हें कोई भी आसपास का निजी संस्थान हाथों-हाथ अपने यहां ले लेगा। इन सभी प्रोफेसरों की जबरदस्त मार्केट वैल्यू है जबकि इसके बरअक्स मुख्यालय में बैठे तथाकथित डॉक्टरों को कोई टके सेर भी न पूछे। ये सभी कॉर्पोरेशन को चिपटी हुई वे जोकें हैं जो मज़दूरों का लहू पी रही हैं।

संस्थान की उत्कृष्ट एवं विस्तृत होती सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यकतानुरूप पर्याप्त स्टाफ़ उपलब्ध कराने की अपेक्षा कॉर्पोरेशन मुख्यालय में बैठे जनविरोधी जीडीएमओ गैंग ने ताजातरीन आदेश से संस्थान के बेहतरीन प्रोफेसर (डॉक्टरों) को कलकत्ता, बेंगलुरू, चेन्नई आदि स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। विदित है कि संस्थान में कुछ प्रोफेसर नियमित हैं और अधिकांश ठेके पर। स्थानांतरित किये गये सभी डॉक्टर नियमित हैं। इनके जाने के बाद नियमित डॉक्टर मात्र 7 बचेंगे। ये सभी डॉक्टर न केवल मरीज़ों के लिये बल्कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे तमाम छात्रों विशेष कर पीजी छात्रों के लिये अति महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।

सभी जानते हैं कि स्थानांतरित किये गये प्रोफेसरों में से कोई भी कॉर्पोरेशन द्वारा दिये गये गंतव्य तक पहुंचने वाला नहीं है। इतना ही नहीं इनके बदले जिनको यहां लाया जा रहा है, वे भी यहां आने वाले नहीं हैं। इसका जीता-जागता उदाहरण सन् 2019 में मुंबई से किये गये 6 डॉक्टरों का तबादला है। वहां के मेडिकल कॉलेज का सत्यानाश करने के लिये 6 प्रोफेसरों का तबादला फ़रीदाबाद कर दिया गया था। इनमें से तीन तो वहां के वहीं इस्तीफ़ा दे गये थे। एक-दो जो आये भी थे वे छुट्टियों पर ही रहकर अपना वक्त पूरा कर गये थे। यानी कि वे न वहां रहे न ही यहां। जीडीएमओ गैंग ने मुंबई ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का सत्यानाश करना था सो खूब तसल्ली से कर दिया।

यदि कोई डॉक्टर दक्षिण भारत से आकर यहां मरीज़ देखने लगे तो क्या होगा? न डॉक्टर मरीज़ की समझेगा और न ही मरीज़ डॉक्टर की। तो ऐसे में भला कौन किसका क्या इलाज कर पायेगा? लेकिन जीडीएमओ गैंग को तो इससे कोई लेना-देना नहीं। उनका तो एकमात्र उद्देश्य मरीज़ों को मिलने वाली सेवा का सत्यानाश करना है। लगता है उन्हें इस बात से भी बड़ी कोफ़्त है कि उनका बसई दारापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अपेक्षाकृत पुराना होने के बावजूद इस नये नवेले संस्थान के सामने कहीं भी नहीं ठहरता। इसलिये भी इसके पर कतरना वे जरूरी समझते हैं।

विदित है कि इस संस्थान की उत्कृष्ट सेवाओं के चलते बढ़ती लोकप्रियता के कारण यहां मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यहां इलाज के लिये आने वालों में न केवल हरियाणा बल्कि दिल्ली व यूपी से भी मरीज़ भेजे जाते हैं। और तो और चंडीगढ़ तथा चेन्नई तक से भी आये मरीज़ स्वस्थ होकर यहां से गये हैं।

जाहिर है कि ऐसे में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ़ की भारी कमी का सामना संस्थान को करना पड़ रहा है। इस कमी को दूर करने के लिये बार-बार मुख्यालय से निवेदन किया जा रहा है अतिरिक्त स्टाफ देने की बजाय मुख्यालय ने ऐसा 'बढ़िया' काम कर दिया है कि मरीज़ों की भीड़ ही नहीं रहेगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब इलाज करने वाले डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो मरीज़ क्या झख मारने को आयेंगे?

दो साल से केन्द्रीय श्रम मंत्री के पद पर विराजमान भूपेन्द्र सिंह यादव क्या यह सब देखने-समझने एवं कुछ कर पाने में बिल्कुल असमर्थ हैं?

सेवा शर्तों के मुताबिक तबादला नहीं किया जा सकता

फैकल्टी भर्ती के लिये 2013 में कॉर्पोरेशन द्वारा विज्ञापित किये गये विज्ञापन के अनुसार फैकल्टी की भर्ती संस्थान विशेष के लिये ही होगी। विज्ञापन द्वारा अलग-अलग नामजद संस्थानों के लिये आवेदन मांगे गये थे। जिन लोगों ने फ़रीदाबाद के लिये आवेदन किया था उन्हें केवल फ़रीदाबाद के लिये, जिन्होंने कलकत्ता, बेंगलुरू अथवा कहीं के लिये भी आवेदन किया था, उन्ही संस्थानों में नियुक्तियां दी गई थीं।

फैकल्टी के मामले में संस्थान विशेष के लिये नियुक्तियां करने की नीति बड़ी सोच-समझकर बनाई गई है। यह नीति केवल ईएसआईसी के लिये नहीं बल्कि तमाम ऐसे बड़े संस्थानों के लिये बनाई गई है, क्योंकि इन संस्थानों में मरीज़ों के इलाज, छात्रों की पढ़ाई के साथ-साथ प्रयोगशालाओं में रिसर्च एवं तरह-तरह के शोधकार्य चलते रहते हैं। इसके लिये फैकल्टी का लगातार अपने संस्थान से जुड़े रहना अति आवश्यक समझा गया है। इस संस्थान में भी बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर के अनेकों प्रोजेक्ट एवं शोध कार्य चल रहे हैं। यहां की फैकल्टी द्वारा किये गये शोध कार्य अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। फैकल्टी के ऐसे उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए अनेकों कॉर्पोरेट्स ने पैसा भी उपलब्ध कराया है। इसी पैसे से अनेकों उपकरण आज अस्पताल में कार्यरत हैं।

एमबीबीएस के बाद की पढ़ाई यानी पीजी की सीटें भी फैकल्टी के हिसाब से ही एनएमसी (नेशनल मेडिकल कमीशन)द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। एक प्रोफेसर को तीन पीजी छात्र तथा एसोसिएट प्रोफेसर को एक छात्र प्रति वर्ष मिलते हैं। इस हिसाब से यहां पर विभिन्न ब्रांचों के 85 पीजी छात्र अपनी पढ़ाई व मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। प्रोफेसरों के तबादले के बाद इन पीजी छात्रों की पढ़ाई का सत्यानाश होना तय है क्योंकि मौजूदा प्रोफेसर तो चले जायेंगे और बदले में आना किसी को नहीं। इतना ही नहीं इन हालात में अगले साल के लिये मिलने वाली पीजी सीटें भी नहीं मिल पाएंगी। परन्तु इन सब बातों से जीडीएमओ गैंग को क्या लेना है? जब इन्होंने खुद ही पीजी की पढ़ाई नहीं की तो वे औरों को भी क्यों पढ़ने देंगे? इनकी यही सोच रिसर्च एवं प्रोजेक्ट्स के बारे में भी रहती है।

जीडीएमओ गैंग

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानी जीडीएमओ। ईएसआई कॉर्पोरेशन में इस पद पर भर्ती होने के लिये एमबीबीएस की डिग्री ही पर्याप्त होती है। इस स्तर के डॉक्टर प्रायः डिस्पेंसरी में आने वाले साधारण मरीजों को देखते हैं। कॉर्पोरेशन की स्थापना के समय बीमाकृत मज़दूरों की संख्या बहुत कम होती थी। डिस्पेंसरी के डॉक्टर जरूरत पड़ने पर, विशेष जांच एवं इलाज आदि के लिये मरीजों को बड़े अस्पतालों को रेफ़र कर दिया करते थे। समय के साथ-साथ बढ़ती जरूरतों के अनुरूप कॉर्पोरेशन में न केवल विशेषज्ञ डॉक्टर भर्ती किये गये बल्कि मेडिकल कॉलेज भी चालू किये गये।

इस अंतराल में जीडीएमओ सेवाकाल की लम्बाई के आधार पर कॉर्पोरेशन के शीर्ष पदों पर काबिज हो गये। संख्या बल तो इनके साथ था ही, मुख्यालय पर भी अधिकार हो जाने से इन्होंने कॉर्पोरेशन को अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। जिस ईएसआई कॉर्पोरेशन का उद्देश्य मज़दूरों से पैसा लेकर उन्हें बदले में बेहतरीन चिकित्सा सेवा देना था, उसे इस गैंग ने केवल पैसा वसूली का साधन मान लिया। चिकित्सा सेवाओं पर होने वाले आवश्यक खर्च को न करके अपने कोष में दिन दूनी- रात-चौगुनी वृद्धि करने में जुट गये। इनकी हठधर्मी का आलम तो यहां तक रहा है कि मेडिकल कॉलेज के डीन पर अंकुश रखने के लिये किसी जीडीएमओ को ही एमएस (चिकित्सा अधीक्षक) बना कर बैठाया जाता रहा है।

इसी एमएस के पास तमाम वित्तीय अधिकार रहते थे। डीन अपनी मर्जी से पानी पीने का गिलास तक नहीं खरीद सकता था। अपनी इसी वित्तीय शक्ति के चलते ये लोग अच्छे-भले अस्पताल का बेड़ा गर्क करते रहे हैं जिसका जीता-जागता उदाहरण बसई दारापुर है। यह सब दादागिरी तो एनएमसी की उस हिदायत के बावजूद चलती रही जिसके अनुसार मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एमएस जीडीएमओ के बजाय वरिष्ठ प्रोफेसर हो सकता है। एनएमसी की कड़ी चेतावनी के बाद यहां के एमएस पद पर एक वरिष्ठ प्रोफेसर को बतौर एमएस नियुक्त किया गया। इस परिवर्तन से जीडीएमओ गैंग में अच्छा-खासा मातम छा गया था।

मुख्यालय में बैठा यह गैंग, अपने वेतन से अंशदान देने वाले गरीब मज़दूरों की भलाई की बाबत सोचने की अपेक्षा हर वक्त इसी उधेड़बुन में लगा रहता है कि किस प्रकार से अच्छे-भले चलते हुए किसी अस्पताल को कैसे बर्बाद किया जाए। मुख्यालय में बैठने की सुविधा के चलते, दो-तीन साल के लिये बतौर डीजी तैनात होने वाले आईएएस अफसरों को ये लोग हर समय उलटा-पुलटा पाठ पढ़ाते रहते हैं। परन्तु पिछले दिनों कुछ बेहतरीन डीजी व श्रम सचिवों ने इन्हें दरकिनार करके मेडिकल कॉलेजों के डीन से सीधी बात करनी शुरू की तो ये बेचारे मन मसोस कर रह गये और अस्पतालों का काफी कुछ उद्धार हो पाया।

गौरतलब है कि किसी मेडिकल कॉलेज का डीन एवं फैकल्टी का चुनाव करने के लिये बाकायदा एक विशेषज्ञ कमेटी साक्षात्कार लेती है। उनकी तमाम शैक्षणिक डिग्रियों एवं अनुभवों का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। लेकिन यह कम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि कॉर्पोरेशन के दसियों मेडिकल कॉलेजों तथा पचासों अस्पतालों को चलाने का जिम्मा मुख्यालय में बैठे इन नालायकों को सौंप रखा है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।